ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने अहम् भूमिका निभाई- अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांचू पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उत्साहवर्धन किया

बीकानेर, (निसं)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे सीमा प्रहरी तेज बारिश, अधिक तापमान, घने जंगल, बर्फीली चोटियों जैसी कठोर परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आश्वस्त

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा चौकियों पर निर्मित 14 महिला बैरकों का ई-लोकार्पण किया, प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन किया तथा सांचू माता मंदिर में पूजा अर्चना की

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बीकानेर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया।

किया कि केन्द्र सरकार भारतीय सीमाओं पर तैनात बीएसएफ को आधुनिकतम तकनीक एवं बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री मंगलवार को बीकानेर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ मौजूद रहे।

सन 1965 में भारत पाक युद्ध के समय सूचना मिली थी कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। तब 3आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम किया था। जवानों ने यह जिम्मेदारी निभाई और पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। उन्होंने कहा, सरकार अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत कर रही है। लेकिन ड्रोन यहां की जमीन पर उतरता है, इसे कौन रिसीव करता है, कौन उसके मटेरियल का उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में आज बेटियां बेटों से दो कदम आगे है। केन्द्र सरकार वर्ष 2030 तक इन बेटियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में बीएसएफ की सीमा चौकियों पर बेटियों के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से आज लोकार्पण हुए 14 बैरक सहित, 67 का काम पूरा हो चुका है। शेष 12 बैरक का कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। देश की सीमा चौकियों पर 200 करोड़ की लागत से 360 बैरक बनाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1096 किलोमीटर लंबी लिटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्ससीएल रोड बनाई जा रही हैं। यह जवानों की आवागमन और कनेक्टिविटी सम्बन्धी चिंता को दूर करेंगी। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर नई डिजाइन की फेंसिंग की जा रही है। सीमा की 180 चौकियों पर पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाने का काम पूरा किया गया है।

इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जवानों के साथ जलपान एवं संवाद भी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई-लोकार्पण किया। उन्होंने प्रहरी शस्त्र गैलरी का अवलोकन कर आधुनिक ड्रोन तकनीक की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री ने सांचू माता मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की तथा देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की तथा खेजड़ी का पौधा लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया और आमजन से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाने का आव्हान किया।

इस दौरान केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन, निदेशक आसूचना ब्यूरो तपन कुमार, सचिव सीमा प्रबंधन डॉ. राजेन्द्र कुमार, बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार सहित, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान मौजूद थे।

दो-तीन दिन में मानसून केरल पहुंचेगा

नई दिल्ली, 26 मई। पिछले चार दिनों से केरल से लगभग 35 किलोमीटर दूर अटके हुए दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले दो-तीन दिनों में आगे बढ़ ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आज (26 मई) केरल पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही, चार दिन आगे-पीछे आने की बात भी कही गयी थी, लेकिन पिछले चार दिनों से मानसून केरल से लगभग 35 किलोमीटर दूर ही अटका हुआ है। हालांकि केरल में बारिश तो हो रही है, मगर मानसून आने के सभी फैक्टर पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मौसम विभाग ने अभी केरल में मानसून आने की घोषणा नहीं की है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने तथा अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है।

240 ''नर्सिंग ट्यूटर'' की भर्ती के लिए रास्ता साफ

- अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि उन 80 पद, जिन पर याचिकाकर्ता संविदा पर काम कर रहे हैं, भर्ती न की जाए, शेष 240 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु की जा सकती है।
- राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवम्बर 2025 के अपने एक आदेश में इन 80 संविदाकर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी थी।

जयपुर 26 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रदेश में नए स्थापित हुए मेडिकल कॉलेजों में 382 ''नर्सिंग ट्यूटर'' पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई होगी। न्यायाधीश आनन्द शर्मा की अदालत ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार 80 संविदा कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी 240 रिक्त पदों पर नर्सिंग ट्यूटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है और विज्ञप्ति जारी कर सकती है। इस मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चित बोहरा पैरवी के लिए पेश हुए।

ज्ञात रहे कि इसी मामले में राज्य सरकार द्वारा 80 ''नर्सिंग ट्यूटरों'' को प्रदेश में नए स्थापित हुए मेडिकल कॉलेजों में संविदा कर्मचारी की तर्ज पर नियुक्त कर रखा था। परन्तु जब रिक्त पदों को भरने की बारी आई, तब संविदा पर भर्ती कर्मचारियों ने पहले सरकार से गुहार की कि उन्हें स्थाई रूप से नियुक्ति दे दी जाए, पर जब वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को विज्ञप्ति के माध्यम से ही भरने का रास्ता चुना तो संविदा पर भर्ती हुए इन कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 25 नवम्बर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इन 80 संविदा कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश सुनाया था जिसके तहत राज्य सरकार पर इन संविदा, कर्मचारियों को उनके पद से हटाने पर रोक लगा दी गई थी।

सभी पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 12 दिसम्बर 2024 को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 240 अतिरिक्त नर्सिंग ट्यूटर पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, परन्तु उन 80 पदों पर, जिन पर याचिकाकर्ता अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं, उन पर नियुक्ति न की जाए, जब तक इस मामले का पूर्ण निस्तारण नहीं किया जाता। इस मामले की अगली सुनवाई 08 जुलाई तय की गई।

बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव 18 जून को

चुनाव आयोग के अनुसार 9 सीटों पर निर्धारित चुनाव तथा नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव होगा

- यह माना जा रहा है कि 9 सीटों पर जीत सुनिश्चित है, पर यदि राजग दस उम्मीदवार चुनाव में उतारता है तो क्रॉस वोटिंग व राजनीतिक खेल की संभावना बढ़ जायेगी।

पटना, 26 मई। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव कराया जाएगा। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई सीट भी शामिल है, जिस पर उपचुनाव कराया जाएगा। यह सीट विधानसभा कोटे से विधान परिषद के लिए भरी जाएगी और निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा।

इसके अलावा, बिहार विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रो. गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। हालांकि इनमें से सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीट पहले से खाली है, क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुके हैं।

चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव और अन्य नौ सीटों के नियमित चुनाव के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है। आयोग के अनुसार, बिहार के साथ-साथ कर्नाटक विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आवश्यक हुआ तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास 201 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 में से नौ सीटों पर राजग की जीत लगभग तय है, जबकि एक सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है।

अन्नाद्रमुक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधायक कुमारवेल और धारापुरम विधायक सत्यभामा पहले ही अपने पदों से इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो चुके हैं। लगातार हो रहे इन इस्तीफों से अन्नाद्रमुक के भीतर असंतोष और बेचैनी बढ़ ती दिखाई दे रही है।

कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर था। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है।

चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकारों को प्रभावित क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल सैंसर व मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली, 26 मई। उच्चतम न्यायालय ने चंबल अभयारण्य में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि ये काम युद्ध स्तर पर किया जाए और छह महीने के अंदर सम्पूर्ण निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से चालू होनी चाहिए। इसके अलावा अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने फर्जी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल वाहन चालक पर ही नहीं, बल्कि वाहन मालिकों और ठेकेदारों पर भी होनी चाहिए। कोर्ट ने अवैध खनन का परिवहन रोकने के लिए उठाये गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है।

बकरीद से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में हर राज्य में कानून के मुताबिक बूचड़खानों के रेगुलेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

पन्ना में कुआं धंसने से 5 मजदूरों की मौत

पन्ना, 26 मई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड में ग्राम बीहरपुरवा के नयापुरवा में मंगलवार को एक खेत पर कुएं की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। इस हादसे में मलबे में दबे पांच मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में तीन मजदूर एक ही परिवार के हैं। ग्राम बीहरपुरवा के नयापुरवा निवासी बिन्नू अहिरवार के खेत पर लगभग 10 दिनों से सात मजदूर कुएं की खुदाई का काम कर रहे थे।

क्वाड सम्मेलन में समुद्री निगरानी व दुर्लभ खनिज उत्खनन पर अहम फैसले हुए

- जयशंकर की मेजबानी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया

नई दिल्ली, 26 मई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एवं भारत के चतुष्कोणीय रणनीतिक गठजोड़ क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज यहां संपन्न बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी, ऊर्जा सुरक्षा तथा दुर्लभ खनिज के उत्खनन, शोधन एवं आपूर्ति श्रृंखला को लेकर अहम फैसले लिए गए।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया।

इस बैठक में तीन पहलों के साथ ही क्वाड की पहलों पर हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई।

तीन पहलों में से एक में क्वाड साझेदारों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों की समुद्री निगरानी का लाभ उठाने के लिए पहली बार हिंद-प्रशांत क्षेत्र समुद्री निगरानी गठजोड़ पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सूचना साझा करने और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें शुरुआती ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर केन्द्रित होगा।

बंगाल में 5 रूपए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए ''होल्डिंग सेंटर'' पहले ही बना दिए हैं।

तथापि, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घुसपैठियों को बस वापस बांग्लादेश भेज दिया जाना चाहिए। राज्य भर में चिन्हित किए गए इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।

इन घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने के लिए सीमावर्ती कस्बों में कतार में लग गए हैं। अब राज्य में घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है।

शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि सरकार की नीति ''पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर भेजो'' (डिटैक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट) है। कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दे दी है और इस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन वामपंथी दलों ने इस नीति का विरोध किया, क्योंकि उन्ही लोगों ने इन घुसपैठियों को यहां आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया था।

विभाजन के समय जहाँ, कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत थी, आज यह बढ़कर 30 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। इनमें भी अल्पसंख्यक आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 1991 के बाद और खासकर 2000 के बाद हुई।

अब बांग्लादेशियों को वापस भेजने की नई सक्रिय नीति के कारण अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। लोग सभी सीमा चौकियों और कस्बों में पहुंच रहे हैं और वहां से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं।

'5 जून को कोई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन्फ्रास्ट्रक्चर और जनहित परियोजनाओं'' के लिए चाहिए, जिनमें रक्षा संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी शामिल है।

दिल्ली जिमखाना क्लब ने केन्द्र के परिसर खाली करने के निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। नोटिस के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब ने केन्द्र को पत्र लिखकर कहा था कि उसके खिलाफ किसी भी अचानक कार्रवाई से उसके कर्मचारियों और सदस्यों सहित, कई हितधारकों पर असर पड़ेगा। क्लब ने केन्द्र से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसे पुनर्वास के लिए ''उपयुक्त स्थान पर वैकल्पिक भूमि'' आवंटित की जाएगी।

यह एक विशिष्ट क्लब है जहां चुनिंदा राजनयिक, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित लोग तथा बुद्धिजीवी एकत्र होते हैं। क्लब ने अपने पत्र में कहा कि उसके लगभग 14,000 सदस्य और उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने क्लब की सुविधाओं के उपयोग के लिए सदस्यता और सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किया है। क्लब में 500 लोग कार्यरत हैं और यहां सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रमों का आयोजन होता है। क्लब ने कहा कि सरकार की किसी भी अचानक कार्रवाई का प्रभाव अनेक हितधारकों पर पड़ेगा।

शिवराज सिंह चौहान की किताब ''अपनापन'' का विमोचन

नई दिल्ली, 26 मई। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैय्या नायडू ने मंगलवार को एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक 'अपनापन' का लोकार्पण किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उनके साथ बिताए गए 35 वर्षों के अनुभवों पर लिखी है। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैय्या नायडू ने कहा कि जब कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होती थी, तब वे कहा करते थे कि मोदी का अर्थ है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया और आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें यह भाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

केन्द्र सरकार ने हाई पावर्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर पोस्ट करते हुए कहा, ''असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल किसी एक राज्य की चिंता नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है''।

समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रभाकर नाओलकर करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शामिका रवि शामिल हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-1 यूनिट) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति के आठ बिंदुओं वाले कार्यादेश (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के अनुसार, यह समिति जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध प्रवासन भी शामिल है, पर व्यापक विचार-विमर्श करेगी। समिति सीमा पार गतिविधियों और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारकों जैसे संभावित कारणों का अध्ययन करेगी।

समिति असामान्य बसावट के पैटर्न का अध्ययन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का विश्लेषण करेगी और अवैध प्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत तथा निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी कार्यप्रणाली की सिफारिश करेगी। समिति सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की भी सिफारिश करेगी, ताकि इस प्रकार की प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी एवं मॉनिटरिंग की जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक जनसांख्यिकी समिति गठित करने की योजना की घोषणा की थी। पिछले वर्ष सितंबर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

'सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लागू किया जा सकता है, जब डॉक्टर केवल सरकारी अस्पतालों में काम करने का विकल्प चुनते है, और इस अतिरिक्त वेतन दिये जाने के कारण प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकते, चूंकि यह विकल्प उनके पास भी उपलब्ध था।

जनता परेशान, यह सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है- पायलट

पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट का अजमेर पहुँचने पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया

अजमेर, 26 मई (निसं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री के मंगलवार को अजमेर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गेगल औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सचिन पायलट का गर्मजोशी से स्वागत किया।

स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके बाद

- कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद सचिन पायलट पुष्कर के लिए रवाना हो गए, जहाँ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है।

सचिन पायलट पुष्कर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हो गए।

मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का मंगलवार को अजमेर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने केन्द्र सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।

पंचायत, निकाय और छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर भी पायलट ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय लगातार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है। कानून के अनुसार जनप्रतिनिधियों के बिना बजट जारी नहीं हो सकता, जिससे प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोहरे इंजन की सरकार बार-बार चुनाव टाल रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और सरकारों को जवाबदेह बनाने का काम करेगी। इस अवसर पर विजय जैन, संग्राम सिंह गुर्जर, राकेश पारीक, नसीम अख्तर इंसाफ, हेमंत भाटी, महेन्द्र सिंह रलावता, शिवप्रकाश गुर्जर, कमल बाकोलिया, अंकुर त्यागी, श्याम प्रजापति, प्रताप यादव, हितेश्वरी टॉक, रेनू मेघवंशी, रश्मि हिंगोरानी, विपिन बैसिल, कैलाश कोमल, वैभव जैन, बलराम शर्मा, निर्मल बैरवाल, नज्जू पठान और दिनेश शर्मा सहित, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908